भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 449

21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसी)

449. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
डॉ. हेमांग जोशी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेष रूप से निवेश को आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के संबंध में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसी) के उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना में विनिर्माण के स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत परिकल्पित प्रस्तावित निवेश, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र और भागीदार विनिर्माताओं की भूमिका सहित इसके कार्यान्वयन ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कोई निवेश प्रस्तावित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को वैश्विक इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माताओं से निवेश (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित) आकर्षित करने तथा भारत को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.03.2024 को अधिसूचित

किया गया था। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक को भारत में ई-चौपहिया विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करनी होंगी, जिसमें न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा तथा अनुमोदन की तारीख से तीसरे वर्ष तक 25 प्रतिशत और पाँचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा।

(ग) से (ङ): एसपीएमईपीसीआई के कार्यान्वयन हेतु, दिनांक 15.03.2024 की स्कीम अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुपूरक विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए। स्कीम अधिसूचना के पैरा-9 के अनुसार, स्कीम के अनुमोदन, समग्र अनुवीक्षण तथा कार्यान्वयन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी स्कीम अनुमोदन समिति गठित की गई है। प्रस्तावित निवेश के संबंध में, स्कीम के अंतर्गत अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****